बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 85 ● नई दिल्ली ● शनिवार 10 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली का तुर्कमान गेट छावनी में तब्दील, पत्थरबाजी के बाद बीएनएसएस की धारा 163 लागू, 1000 जवान तैनात

नई दिल्ली। शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि तुर्कमान गेट इलाके के पास हुई पत्थरबाजी की घटना के मद्देनजर दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की है। बुधवार को मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान के बाद पत्थरबाजी की घटना घटी। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मस्जिद के बाहर और आसपास के इलाकों में 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।

दिल्ली ने आज तोड़ दिए ठंड के सारे रिकॉर्ड, इस मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा टेंपरेचर

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया जबकि शहर के कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई. न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम में सामान्य तापमान से लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस कम था और यह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही. शहरभर के मौसम स्टेशनों ने भी सुबह के शुरुआती घंटों में हल्की बारिश दर्ज की, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा. स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम था, जबकि पालम में 5.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम था. लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम था, जबकि रिज स्टेशन पर 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम था. सूचीबद्ध स्टेशनों में आयानगर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो औसत से 1.2 डिग्री कम था.

पालम और रिज स्टेशन पर कोई बारिश दर्ज नहीं

सफदरजंग और लोधी रोड में पिछले 24 घंटों में सुबह साढ़े आठ बजे तक मामूली बारिश दर्ज की गई, जबकि आयानगर में 0.8 मिमी बारिश हुई. इसी अवधि के दौरान पालम और रिज स्टेशन पर कोई बारिश दर्ज नहीं की गई. क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार, दिल्ली में अक्षरधाम, लोधी रोड, नेहरू स्टेडियम, आर के पुरम, डिफेंस

कॉलोनी, लाजपत नगर, तुगलकाबाद, इग्नू, आयानगर और डेरामंडी समेत कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपने पूर्वानुमान बुलेटिन में कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान है. विभाग ने कहा, आज सुबह कड़ाके की ठंड है लेकिन अभी तक शीत लहर की कोई आशंका नहीं है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

बृहस्पतिवार को मौसम की तीसरी सबसे ठंडी सुबह रही थी, क्योंकि शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में पारा गिरकर 5.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है. इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान चार और पांच दिसंबर को दर्ज किया गया था, जब तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. एक दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस था, जिससे बृहस्पतिवार का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस इस सर्दी में अब तक दर्ज किया गया तीसरा सबसे कम तापमान था. दिल्ली में इस साल का पहला शीत दिवस छह जनवरी को दर्ज किया गया था, जब अधिकतम तापमान गिरकर 15.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम के औसत से 3.3 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम था. बुधवार को भी राजधानी में भीषण ठंड का प्रकोप जारी था. अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम था, और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो मौसमी औसत से 1.7 डिग्री कम था. विभाग के अनुसार, शीत दिवस की स्थिति तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे गिर जाता है.

इस बीच, दिल्ली की वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में बनी रही, और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 325 दर्ज किया गया. छब्बीस निगरानी केंद्रों ने अत्यंत खराब वायु गुणवत्ता की सूचना दी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वर्गीकरण के अनुसार, एक्यूआई शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

अमित शाह कार्यालय के बाहर टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया तो भड़कीं महुआ मोइत्रा

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक तापमान उस समय अचानक बढ़ गया जब तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और कीर्ति आजाद भी शामिल थे। प्रदर्शन का कारण राजनीतिक रणनीति से जुड़ी संस्था आई-पैक और उससे संबंधित लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी थी।

तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और चुनावी तैयारियों को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है। हालात तब और गंभीर हो गए जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में लेना शुरू किया। सांसदों को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई की

कड़ी निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए डर और दमन का सहारा लिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक मंशा नहीं है। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। उधर, पुलिस हिरासत से छूटने के बाद तृणमूल सांसदों ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उधर सांसद कीर्ति आज़ाद ने I-PAC ऑफिस पर ईडी की छापेमारी पर कहा, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह के कार्यालय के बाहर ईडी की छापेमारी के विरूद्ध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन प्रस्न उठता है कि ईडी की रेड विशेष तौर पर और जबरदस्ती तौर पर क्यों किए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अमित शाह ने खुद कहा था कि हिमंत बिस्वा सरमा को जेल में डालेंगे, अजीत पवार के विरूद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70 हजार करोड़ का घोटाला हुआ था, बंगाल के एक नेता सुवेंदु अधिकारी को भी 5 लाख रुपये की हेरा-फेरी करते देखा गया था। क्या ईडी केवल उन विरोधियों के खिलाफ काम कर रही है जिसके खिलाफ वे (भाजपा) जीत नहीं सकते? क्या भाजपा की हिम्मत नहीं कि वे वहां (पश्चिम बंगाल) आकर ममता बनर्जी के खिलाफ जीत सकें? कीर्ति आजाद ने कहा कि आज 2 बजे हमारी नेत्री कोलकाता की सड़कों पर मार्च करेंगी ईडी के असंवैधानिक कार्रवाई पर। गैर राजनीतिक रूप से हम पर जो कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं कहना, यह जो भी किया गया है, जो भी रेड हुई है वह उचित नहीं अनुचित है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, हमें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया है। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने अपने प्रवर्तन निदेशालय, वसूली निदेशालय को हमारी पार्टी पर लूटपाट करने, राजनीतिक जासूसी करने और हमारे चुनाव डेटा और दस्तावेज़ चुराने के लिए भेजा। वे हमें, जन प्रतिनिधियों को, यहाँ घसीटकर लाए, ईडी सिर्फ़ विपक्ष के लिए ही क्यों है? किसी और विपक्षी नेता में वह हिम्मत नहीं है जो दीदी (ममता बनर्जी) ने कल हमारी पार्टी के दस्तावेज़ बचाने के लिए किया।

पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही विपक्षी पार्टियां... तुर्कमान गेट मामले में भड़की बीजेपी! इंडी अलायंस को बताया 'रावलपिंडी गठबंधन'

नई दिल्ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में ऐतिहासिक फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर उठे विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्ष और आलोचकों के उन आरोपों का कड़ा खंडन किया है जिनमें मस्जिद को ध्वस्त करने का दावा किया गया था। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इसी दावे का वीडियो साझा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है और भारत-भारत गठबंधन को रावलपिंडी गठबंधन करार दिया है। पूनावाला ने इन आरोपों को फर्जी, दुष्प्रचार और उकसावा बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आलोचकों के आरोपों के विपरीत मस्जिद को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। यह विवाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर मस्जिद के पास स्थित अनधिकृत व्यावसायिक ढांचों जैसे कि निदान केंद्र और विवाह हॉल को हटाने के अभियान से उपजा है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने पत्रकारों से कहा कि फैज-ए-इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। धार्मिक संरचना को कोई क्षति नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक वैध अतिक्रमण-विरोधी कार्रवाई को धार्मिक संरचना पर हमले के रूप में चित्रित करने के लिए जानबूझकर झूठी कहानी फैलाई गई थी। उन्होंने कहा कि फैज-ए-इलाही मस्जिद को ध्वस्त किए जाने या मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के बारे में फैलाई जा रही सारी झूठी बातें और दुष्प्रचार पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत के आदेशों के तहत केवल अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया था। पूनावाला ने आरोप लगाया कि दुष्प्रचार अभियान आकस्मिक नहीं बल्कि सुनियोजित था। उन्होंने दावा किया कि इस कहानी को पाकिस्तान ने अपनाया और पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, जिससे इसके स्रोत पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा अब ऐसा लगता है कि दिशा और पटकथा कहीं और से आई थी, और विपक्ष केवल उस पटकथा को सुना रहा था। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान और विपक्षी नेताओं के बीच सुर और ताल - या समन्वय - स्पष्ट था।

दिल्ली विधानसभा के बाहर आप का जोरदार प्रदर्शन, आतिशी के वीडियो को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आप विधायक संजीव झा ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष के नेता आतिशी से जुड़े एक फर्जी वीडियो को प्रसारित करके दिल्ली के प्रमुख मुद्दों, जैसे कानून व्यवस्था, दूषित पानी, प्रदूषण और यमुना नदी से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर गलत ट्रांसक्रिप्शन के साथ वीडियो साझा किया। एनआईए से बात करते हुए झा ने कहा कि दिल्ली में कई मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, दूषित पानी, यमुना नदी, प्रदूषण। इन समस्याओं से बचने के लिए भाजपा ने एक फर्जी वीडियो बनाया है और उसमें गुरु साहब का नाम घसीटा है ताकि असली मुद्दों पर चर्चा न हो सके... दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गलत ट्रांसक्रिप्शन के साथ वीडियो पोस्ट किया है। हम उनके और वीडियो साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उन्हें छह महीने के लिए निलंबित किया जाना चाहिए। एक दिन पहले, दिल्ली विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब भाजपा विधायकों ने विपक्ष के नेता आतिशी द्वारा एक सिख गुरु पर कथित टिप्पणी के विरोध में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद आप विधायक पोस्टर लेकर और नारे लगाते हुए विधानसभा में घुस गए और कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी (सोमवार) को शुरू हुआ और 8 जनवरी तक चलेगा। आप विधायक और विपक्ष के उपनेता मुकेश अहलावत ने आतिशी पर लगे आरोपों और इस मामले से जुड़े वीडियो के प्रसार के संबंध में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा। अपने पत्र में अहलावत ने कहा, कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, जिससे यह सवाल उठता है कि उन्होंने वीडियो फुटेज कैसे प्राप्त किया। उनके द्वारा ट्वीट किए गए फुटेज में भी यह स्पष्ट है कि विपक्ष के नेता आतिशी कह रही हैं, तो कृपया चर्चा करें। आप सुबह से क्यों भाग रहे हैं? आप कह रहे हैं, कुत्तों का सम्मान करो, कुत्तों का सम्मान करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इस मामले पर चर्चा की अनुमति दें।

हाई कोर्ट ने दी अल्पसंख्यक स्कूलों को राहत, फीस रेगुलेशन को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी को तलब

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अलग-अलग अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से जवाब मांगा। इन याचिकाओं में एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए सरकारी मंजूरी को जरूरी बनाया गया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया और सुनवाई मार्च तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता स्कूल मैनेजमेंट को छह हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की भी इजाज़त दी। बेंच ने कहा कि स्कूल 10 जनवरी की पिछली डेडलाइन के बजाय 20 जनवरी तक अपने द्वारा ली जाने वाली फीस को रेगुलेट करने के लिए स्कूल-लेवल कमेटियां बना सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा प्रस्तावित फीस कमेटी को जमा करने की आखिरी तारीख पहले तय की गई 25 जनवरी

के बजाय 5 फरवरी तक बढ़ा दी जाएगी। अलग-अलग अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं में दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने गुरुवार को भी कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अल्पसंख्यक स्कूलों ने तर्क दिया कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुछेद 30 का उल्लंघन करता है, जो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने तर्क दिया कि अल्पसंख्यक स्कूलों को अपनी फीस तय करने का अधिकार है और सरकार केवल यह सुनिश्चित कर सकती है कि ली जाने वाली फीस बहुत यादा न हो। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सरकार से पहले मंजूरी लेना गलत है और यह नियम अनुछेद 30 का साफ उल्लंघन है। हालांकि, शिक्षा निदेशालय की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने नए कानून का बचाव करते हुए कहा कि अनुछेद 30 की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार द्वारा रेगुलेटरी उपायों की इजाज़त देते हैं। याचिका में दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा 24 दिसंबर, 2025 को जारी एक आदेश को भी चुनौती दी गई थी। आदेश में प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों को 10 जनवरी, 2026 तक एक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, पांच माता-पिता, तीन टीचर और इन्स्पे का एक प्रतिनिधि शामिल होना जरूरी था। स्कूलों की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि उन्होंने नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। रोहतगी ने दलील दी कि इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि यह एक्ट के खिलाफ है और इसलिए गैर-कानूनी है।

रैगिंग शिक्षित समाज का कलंक

देश में रैगिंग प्रतिबंधित है। साल 2001 में रैगिंग पर बैन लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें छात्रों को चिढ़ाने, उनके साथ बुरा बर्ताव, उन्हें परेशान करना, छेड़ना, गलत काम करने के लिए बाध्य करना, सीनियर होने के नाते उनसे अनुचित काम कराना, अपराध है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके साथ कुछ भी ऐसा करना, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, परेशानी हो या उनकी मानसिक सेहत प्रभावित हो, इसे अनुशासनहीनता माना जाता है। साल 2009 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक शराबी सीनियर ने अपने जूनियर छात्र पर हमला किया था। अमन नाम के इस स्टूडेंट की मौत हो गई थी, इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग से निपटने के लिए सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आरके राघवन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने रैगिंग से निपटने के लिए कॉलेजों में दिशा-निर्देश तैयार किए। रैगिंग आज भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में समस्या बनी हुई है। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट में यूजीसी के हवाले से कहा गया है कि साल 2022 से लेकर 2023 के बीच में एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर रैगिंग की 858 शिकायतें मिली थीं। यह संख्या साल 2021-22 में 582 थी। 1 जनवरी, 2023 से 28 अप्रैल, 2024 के बीच शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की 1,240 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 82.18 प्रतिशत शिकायतें छात्रों ने दर्ज कराईं, 17.74 प्रतिशत छात्राओं ने और 0.08 प्रतिशत ट्रांसजेंडर वर्ग के स्टूडेंट ने शिकायत की। जनवरी 2018 से अगस्त 2023 के बीच रैगिंग के कारण कम से कम 25 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। सीनियर छात्र, अपना दबदबा दिखाने के लिए रैगिंग करते हैं। डर की वजह से जूनियर छात्र, अपनी शिकायतें नहीं दर्ज करा पाते हैं। जो छात्र बड़े राजनीतिक पकड़ वाले होते हैं वे इसकी धौंस दिखाकर छात्रों को डराते हैं। कुछ लोग गुंडों के समर्थन की वजह से अपना दबदबा दिखाते हैं। रैगिंग के दर्ज मामले बेहद कम होते हैं, पुलिस जांच और गिरफ्तारी की नौबत कई मामलों में कभी नहीं आती। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की रहने वाली 19 साल की एक दलित छात्रा की 26 दिसंबर 2025 को मौत हो गई थी। परिजनों के मुताबिक, वह पिछले करीब दो महीनों से गंभीर मानसिक तनाव और डिप्रेशन में थी और इस दौरान अलग-अलग अस्पतालों में उनका इलाज भी चला। छात्रा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रताड़ना का शिकार हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज की तीन छात्राओं और एक प्रोफेसर ने उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ती चली गई। पिता की शिकायत के आधार पर धर्मशाला पुलिस ने यौन उत्पीड़न और जानबूझकर चोट पहुंचाने से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75, 115(2), 3(5) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। छात्रा के पिता का दावा है कि उन्होंने कई बार इस बारे में आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि किस स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जाए। धर्मशाला के बाद मंडी में रैगिंग का मामला सामने आया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज एवं अस्पताल नेरचौक में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के दो प्रशिक्षु डाक्टरों ने द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु डॉक्टर के छात्रावास के कमरे में घुसकर पिटाई की। दोनों आरोपियों पर रैगिंग करने का आरोप भी लगाया था। शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने जांच में दोनों आरोपियों पर छात्रावास के कमरे में घुसकर जूनियर प्रशिक्षु डॉक्टर की पिटाई किए जाने के आरोप सही पाए गए। आगरा के एसएन मेडिकल कालेज में भी रैगिंग का मामला सामने आया है। एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र ने चार सीनियर छात्रों पर कार में बैठाकर ले जाने से मना करने पर पिटाई का आरोप लगाया है। छात्र ने अपने भाई को बुला लिया मगर आरोपियों ने उसको भी पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत पर थाना एमएम गेट में चार मेडिकल छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जीवन के असहाय पक्ष अगर कालेज में बिखरे या कानून की नजर में उलझे, तो न समाज का घर आबाद है और न ही देश का सही हाल है। क्या रैगिंग में संलिप्त छात्राएं सुरक्षा में रहीं और क्या कोई अध्यापक अपनी नीच हरकतों से कालेज का ईमान बेचता रहा। आखिर हो क्या रहा और होता क्या रहा। आपसी परिचय या सहजता के नाम पर किसी विद्यार्थी को इस हद तक प्रताड़ित करना कि वह उसके लिए जानलेवा साबित हो, क्या एक सामंती कुंठा का परिचायक नहीं है शारीरिक और मानसिक यातना दिए जाने की वजह से किसी विद्यार्थी की जान जाने की घटनाएं अक्सर व्यापक चिंता का कारण बनती रही हैं और इस पर हर स्तर में रोक लगनी चाहिए। रैगिंग लेने वाले छात्रों की मनोवृत्ति बहुत हद तक, उनके परिवेश पर निर्भर करती है। वे कहां से आते हैं, कैसे उनके माता-पिता का व्यवहार है, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से वे हैं। कुछ युवा जब स्कूलों में पहुंचते हैं और अपने सामाजिक पहुंच या ताकत की वजह से कुछ और छात्रों का संरक्षण उन्हें मिलता है तो वे अपनी मनोवृत्ति दिखानी शुरू करते हैं। उन्हीं छात्रों को यदा निशाना बनाया जाता है, जो थोड़े छोटे-सहमे से रहते हैं। कुछ छात्र सीधे गांव या एकाकी परिवारों से निकलकर चमक-दमक वाले कॉलेज में आते हैं। वे कुछ दिन असहज होते हैं और ऐसे में जब उन्हें रैगिंग या किसी सीनियर साथी के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वे मनोवैज्ञानिक तौर पर टूट जाते हैं। ये छात्र अपने परिवार से भी दूर होते हैं और वे समूह के सामने अपमानित होने की वजह से आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों के पास एंटी रैगिंग समितियां नाम की होती हैं। जब तक भारतीय न्याय संहिता में इसे संगीन और गंभीर अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसी घटनाएं थमेंगी नहीं। बिना कठोर कानूनी नियमों के यह संभव भी कि रैगिंग खत्म हो जाएगी, कोरी कल्पना है। इसे खत्म करना है तो पहले इसे अपराध मानना अनिवार्य है।

साल 2009 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक शराबी सीनियर ने अपने जूनियर छात्र पर हमला किया था। अमन नाम के इस स्टूडेंट की मौत हो गई थी, इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग से निपटने के लिए सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आरके राघवन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने रैगिंग से निपटने के लिए कॉलेजों में दिशा-निर्देश तैयार किए।

सम्पादकीय...

अमेरिकी धमकियां

अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर वैश्विक व्यापार में नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस कदम को सीधे तौर पर भारत, चीन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों के खिलाफ दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका पहले से ही भारत पर ऊंचे टैरिफ लागू कर चुका है लेकिन इसके बावजूद भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा है और अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। देखा जाये तो अमेरिकी राजनीति में आक्रामक व्यापार नीति की वापसी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर की टैरिफ भाषा जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है जिससे यह संकेत भी मिला है कि वह जलवायु और व्यापार दोनों मोर्चों पर बहुपक्षीय सहयोग से पीछे हट रहा है। अमेरिका की इस रणनीति से सिर्फ भारत या चीन ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ भी असहज है और वहां भी अमेरिकी धमकियों को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। वैसे भारत की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में अलग दिखाई देती है। हालिया आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात तीन वर्षों की सबसे तेज दर से बढ़ा है। घरेलू मांग में मजबूती, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं, विनिर्माण को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने से भारतीय उद्योग को नया आत्मविश्वास मिला है। साथ ही मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देकर और सुधारों को तेज कर यह संदेश दिया है कि बाहरी दबावों के आगे झुकने की बजाय भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा। हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की इस आक्रामक नीति से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ने की आशंका है। यूरोपीय संघ के लिए यह चेतावनी है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी को भी निशाना बना सकता है। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वह दबाव की कूटनीति से नहीं बल्कि आर्थिक ताकत से जवाब देगा। देखा जाये तो अमेरिका का 500 प्रतिशत टैरिफ का शोर दरअसल डर की राजनीति है। यह उस व्यवस्था की घबराहट को दिखाता है जो दुनिया के बदलते आर्थिक संतुलन को स्वीकार नहीं कर पा रही। भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वह न तो किसी के सामने झुकने को तैयार है और न ही टकराव की बेकार लड़ाई में पड़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति साफ है यानि सीधी भिड़ंत नहीं बल्कि निरंतर प्रहार किया जाये। देखा जाये तो मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो सुधार किए हैं वे आज इस संकट के समय ढाल बनकर सामने आ रहे हैं। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं हों या विदेशी निवेश के लिए नियमों का सरलीकरण हो, हर कदम का मकसद एक ही है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। घरेलू उपभोक्ता बाजार की ताकत को सरकार ने रणनीतिक हथियार में बदला है। जब बाहरी बाजार दबाव बनाते हैं तब भीतर की मांग अर्थव्यवस्था को संभाल लेती है। यदि अमेरिका सचमुच भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाता है तो मोदी के पास कई विकल्प हैं। पहला उपाय है निर्यात बाजारों का और विविधीकरण। हम आपको बता दें कि भारत पहले ही एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दूसरा उपाय है घरेलू विनिर्माण को और आक्रामक समर्थन। तीसरा उपाय है व्यापार समझौतों को तेज करना ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो। चौथा उपाय है विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई। वैसे अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके लिए भी जोखिम भरा है। यूरोपीय संघ और चीन के साथ एक साथ टकराव वैश्विक मंदी को न्योता दे सकता है। भारत इस पूरे खेल में संतुलन की भूमिका निभा रहा है। न तो आंख दिखा रहा है और न ही आंख झुका रहा है। यही रणनीतिक परिपक्वता है। देखा जाये तो डोनाल्ड ट्रंप की शैली टैरिफ धमकी और दबाव पर आधारित रही है लेकिन मोदी की शैली नीतियों और सुधारों पर टिकी है। दोनों नेताओं के बीच यही मूल फर्क है। भारत ने दिखा दिया है कि टैरिफ से डर कर फैसले नहीं बदले जाते बल्कि अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया जाता है कि टैरिफ बेअसर हो जाएं। उधर, अमेरिका के सौर गठबंधन से हटने का फैसला भी यही बताता है कि वह सहयोग की नहीं बल्कि नियंत्रण की राजनीति चाहता है। इसके उलट भारत बहुपक्षीय सहयोग का पक्षधर रहा है। यही कारण है कि आज भारत की आवाज को ग्लोबल साउथ की आवाज माना जा रहा है। देखा जाये तो आज भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास की कहानी है। निर्यात का बढ़ना, घरेलू मांग का मजबूत होना और सुधारों की निरंतरता यह सब बताता है कि भारत सही दिशा में है। अमेरिका चाहे जितनी भी ऊंची दीवार खड़ी करे भारतीय अर्थव्यवस्था उसके ऊपर से रास्ता निकाल लेगी। साथ ही यूरोपीय संघ और चीन के लिए भी यह समय आत्ममंथन का है। अमेरिकी दबाव के आगे झुकना समाधान नहीं है। भारत ने यह रास्ता दिखा दिया है कि आर्थिक मजबूती ही सबसे बड़ा जवाब है। इसलिए यह साफ है कि टैरिफ की राजनीति अल्पकालिक हथियार है जबकि सुधार और आत्मनिर्भरता दीर्घकालिक शक्ति है। मोदी की नीतियां इसी दीर्घकालिक सोच पर आधारित हैं। अगर अमेरिका 500 प्रतिशत टैरिफ का हथौड़ा उठाता है तो भारत के पास नीति सुधार, उपभोक्ता शक्ति और वैश्विक साझेदारी की पूरी ढाल मौजूद है। यही वजह है कि शोर चाहे जितना भी तेज हो, भारत की चाल शांत लेकिन घातक बनी हुई है। बहरहाल, अमेरिका चाहे यह कह दे कि भारत के साथ समझौता इसलिए अटका क्योंकि मोदी ने फोन नहीं किया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। मोदी ऐसे नेता नहीं हैं जो दबाव में आकर या किसी के इशारे पर फैसले लें। भारत की नीति फोन कॉल से नहीं, राष्ट्रीय हित से तय होती है। अगर शर्तें देश के हित में नहीं हैं, तो मोदी पीछे हटने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि भारत आज आत्मविश्वास के साथ दुनिया से बात करता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि नया भारत सम्मान चाहता है, आदेश नहीं। मोदी की विदेश नीति साफ है, बराबरी पर बात होगी, दबाव में नहीं।

भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां, इसके बावजूद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर गुड न्यूज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर दादागिरी भी भारत की आर्थिक रफ्तार को रोक नहीं पा रही। हालांकि भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार गुड न्यूज मिल रही है। पहले भारत ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया और अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिएजीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया गया है जो पिछले वित्त वर्ष के 6.5 प्रतिशत से ज्यादा है। इस वर्ष की वृद्धि दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहित कई विश्लेषकों द्वारा वर्ष की शुरुआत में लगाए गएअनुमानों से कहीं अधिक है। भारत की जीडीपी में वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में पिछले वर्ष के 4.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि के कारणहोगी। हालांकि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाएगए 50 प्रतिशत टैरिफ के कई समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। भारत की नाममात्र वृद्धि दर आखिरी बार महामारी के वर्ष 2020-21 में थी जब अर्थव्यवस्था में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी। महामारी से निकलने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटआई और भारत पूरी दुनिया में तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में कृषि सैक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा। अलग-अलग आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे तेज वृद्धि सेवा क्षेत्र में देखी जा रही है। इस क्षेत्र की वृद्धि दर 2025-26 में 9.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2024-25 में 7.2 प्रतिशत थी। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं तथा सार्वजनिक प्रशासन- सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर इससे भी अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर है, जबकि निर्माण और उपयोगिता क्षेत्रों की वृद्धि दर धीमी है। दूसरी ओर, उपभोग और निवेश दोनों गतिविधियों में अच्छी वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि इस वर्ष वृद्धि दर में तेजी आई है, फिर भी कुछ चिंताजनक बातें हैं। नाममात्र जीडीपी की वृद्धि दर केवल 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह केंद्रीय बजट में अनुमानित 10.1 प्रतिशत से काफी कम है। यह लगातार दूसरा वर्ष होगा जब नाममात्र वृद्धि दर 10 प्रतिशत से कम रहेगी। समय के साथ नाममात्र वृद्धि दर में कमी का सरकार के ऋण घाटे की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। मोदी सरकार ने लगातार कर सुधार करते हुए अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने की कोशिश की और अमेरिका द्वारा डाली जा रही रुकावटों के बावजूद दुनिया में नए बाजारों की तलाश की और उसे सफलता भी मिली। जीएसटी सुधारों से उत्पादों की कीमतें घटीं और उत्सव सीजन पर भारतीयों ने जमकर खरीदारी की जिससे बाजार तो गुलजार हुए ही खपत भी बढ़ी। जिसके चलते कम्पनियों का उत्पादन भी बढ़ा और अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर बन गई। हालांकि भारत के सामने चुनौतियां बरकरार हैं। वर्तमान मूल्यों के विशुद्ध संदर्भ में देखें तो अर्थव्यवस्था के 357.14 लाख करोड़ रुपये के आकार तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2025-26 के बजट में अनुमानित स्तर से थोड़ा अधिक है। हालांकि राजस्व वृद्धि कमजोर रहने के कारण राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4 फीसदी पर नियंत्रित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चूंकि सरकार अगले वित्तीय वर्ष से ऋण-जीडीपी अनुपात को राजकोषीय लक्ष्य के रूप में अपनाने वाली है, इसलिए अब नॉमिनल वृद्धि पर अधिक ध्यान आकर्षित होगा। आने वाली तिमाहियों में मुद्रास्फीति दर अपने वर्तमान निम्न स्तर से ऊपर जाने की उम्मीद है, जो नॉमिनल वृद्धि में सुधार करने में मदद करेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अगले महीने संशोधित आधार के साथ नई जीडीपी शृंखला जारी करेगा। बताया जा रहा है कि यह वर्षों से अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों द्वारा वर्तमान शृंखला को लेकर जताई जा रही चिंताओं का समाधान करेगा। सांख्यिकी विभाग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए भी नई शृंखला जारी करेगा। इस प्रकार समग्र रूप से भारत में आर्थिक गतिविधियों और कीमतों को मापने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। यद्यपि आधार वर्ष में बदलाव और जीडीपी मापने की पद्धति में परिवर्तन के बावजूद यह मानना कठिन नहीं है कि अगला वित्त वर्ष अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार आने वाले वर्ष का प्रबंधन कैसे करना चाहती है यह कुछ सप्ताह बाद आने वाले बजट से स्पष्ट हो जाएगा। चुनौतियां मुख्यतः बाहरी मोर्चे से उत्पन्न हो रही हैं। महीनों की वार्ताओं के बावजूद, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अनिश्चित बना हुआ है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि परस्पर लाभकारी समझौता कितनी जल्दी हो पाता है। मुख्य चुनौती मुद्रा का कमजोर होना है। इंडिया रेटिंग्स का अनुमान है कि वर्ष 26-27 में रुपया औसतन 92.3 प्रतिशत अमेरिकी डॉलर रहेगा। भारत यूरोपीय संघ के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते के जल्दी होने की उम्मीद कर रहा है। यदि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में देरी होती है तो भुगतान संतुलन के मोर्चे पर भारी दबाव बन सकता है जो रुपए के कमजोर होने में नजर आ रहा है। शेयर बाजार लगातार घाटे में चल रहा है। 2025 में विदेशी निवेशकों ने 20 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्यों के भारतीय शेयर बेचे और यह सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। अगले वित्त वर्ष में वृद्धि की गति बनाए रखने के लिएघरेलू और बाहरी मोर्चों पर लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीडीपी तेजी से बढ़ रही है फिर भी निजी निवेश सीमित है। मौजूदा क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग न होने के कारण भारतीय कम्पनियों ने ऋण कम करने, नकदी बचाकर रखने का विकल्प चुना है।

स्त्री बुद्धिजीवी और पुरुष बुद्धिजीवी

गुलमोहर किताब द्वारा आयोजित इस कहानी पाठ कार्यक्रम की शुरुआत लेखक अध्यापक लालिमा सिंह की किताब की उपलब्धि पर चर्चा से हुई। उनकी किताब प्यार को बंजारन तलाश गुलमोहर किताब से 2025 में प्रकाशित हुई। किताब की वजह से वह पिछले 30 साल से बिछड़े अपने बेटे से मिल पाईं। इसके बाद अजय सिंह ने इस डिस्क्लेमर के साथ कहानी पढ़ना शुरू किया कि यह रचना व्यस्कों के लिए है। यह कहानी स्त्री बुद्धिजीवी और पुरुष बुद्धिजीवी के बीच घूमती है। इस बहाने मौजूदा दौर के तानाशाही नफरती शासन को विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। इस कहानी का राजनीतिक एजेंडा बहुत बोल्ड है और परंपरा से हटकर नेताओं का नाम सहित-पहचान सहित जिक्र है। किरदारों के प्रेम संबंधों-यौन संबंधों में स्टेटस वर्चस्व के संघर्ष में गुंथी कहानी मौजूद निजाम पर तीखे कटाक्ष करती है। लेखक-आलोचक प्रोफ़ेसर बजरंग बिहारी तिवारी ने कहा कि यह कहानी मौजूदा दौर में राजनीति और स्त्री और पुरुष के संबंधों को दर्शाती है। कहानी में इस बात की गूंज है कि पर्सनल इज पोलिटिकल। उन्होंने कई उद्धरणों के जरिए यह बताया कि इसमें प्रेम प्रसंगों के बहाने बड़ी बहस की ओर पाठकों को खींचने की कोशिश की गई है। ये प्रसंग मीठी गोली की तरह इस्तेमाल किये गये हैं, ताकि मौजूदा दौर पर लोग सोचने के लिए मजबूर हों। कहानी अच्छी है, लेकिन ब्योरों को संक्षिप्त किया जा सकता है। लेखक-शिक्षिका लालिमा सिंह ने कहा - कहानी मौजूदा दौर को बखूबी रेखांकित करती है। कहानी यह दर्शाती है कि मौजूदा दौर में स्त्री-पुरुष संबंध कितने जटिल और कठिन हो गए हैं। कहानी में वर्चस्व और आजादी को लेकर द्वंद्व है। हालांकि यह सोचना चाहिए कि क्या एक आम आदमी इन द्वंद्वों को समझ पाएगा। नाटककार राजेश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहानी बहुत सशक्त है और गहरे सवाल उठाती है। इस तरह की बोल्ड रचनाओं को लिखने से आजकल लोग बच रहे हैं। कहानी मौजूदा दौर के राजनीतिक परिदृश्य की है। इसमें स्त्री-पुरुष प्रेम और यौन संबंधों को लेकर स्त्री बुद्धिजीवी और पुरुष बुद्धिजीवी में बहस दी गई है। कहानी कहने का अंदाज नया है। गुलमोहर किताब के प्रभारी पत्रकार उपेंद्र स्वामी ने कहा कि यह स्थिर दृश्यों वाली कहानी है। इस कहानी में अजय सिंह की लंबी कविता- करिश्मा कपूर ने कहा, हकीकत में लड़कियां टैक्सी ड्राइवर के साथ नहीं भागा करतीं—की छाप है, उसका विस्तार है। कहानी कई जरूरी सवाल उठाती है, जो हमारे समय से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। कवि-पत्रकार मुकुल सरल ने कहा कि कहानी सामयिक और नये अंदाज में कही गई है। कहानी में स्त्री-पुरुष प्रेम और यौन संबंधों में जो बहस की गई है उसमें कथन और संवाद के स्तर पर और विस्तार हो सकता था। आज के राजनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करती यह एक महत्वपूर्ण कहानी है। सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक राज वाल्मीकि ने कहा कि इस कहानी की भाषा शैली बहुत अच्छी है। एक सिटिंग में पढ़ी जा सकती है।

'दरियादिली' या 'माफी' की भावना प्रशासनिक कठोरता पर भावनात्मक संबंधों और पारस्परिक पहचान की जीत दिखाती है

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में घटित हुई मारपीट की घटना और उसके बाद के घटनाक्रम - निलंबन, बर्खास्तगी, चिकित्सकों की हड़ताल और फिर सामाजिक-राजनीतिक हस्तक्षेप से सुलह को केवल दो व्यक्तियों के बीच की झड़प के रूप में देखना इसकी गंभीरता को नजरअंदाज करना है। यह घटना एक दर्पण है, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, नैतिकता, सार्वजनिक सेवा के संकट और सामाजिक शक्ति-संरचनाओं की जटिल बुनावट को दिखाती है। इसे समग्रता में समझने के लिए हमें व्यक्तिगत दोष से आगे बढ़कर उन व्यवस्थागत दरारों को भी देखना अनिवार्य है, जिनमें यह विवाद पनपा। और इसे पूरी तरह समझने के लिए, हमारी लोकप्रिय संस्कृति विशेषकर हिंदी सिनेमा ने जो चिकित्सकों के स्टीरियोटाइप्स गढ़े हैं, उन पर नजर डालना भी उतना ही जरूरी है। हिंदी फिल्में 'कबीर सिंह' और 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' इस बहस के दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ी हैं, और आईजीएमसी की घटना इन दोनों के बीच के संघर्ष की वास्तविक अभिव्यक्ति लगती है। दरअसल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शिमला एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डॉक्टर द्वारा मरीज को थप्पड़ मारते देखा गया। यह घटना 22 दिसंबर, 2025 को अस्पताल के पल्मोनरी वार्ड में डॉक्टर राघव नारूला और एक मरीज अर्जुन पवार के बीच हुई। मरीज अर्जुन का कहना है कि पूरा विवाद 'तू' कहने से शुरू हुआ। यह बात दुरुस्त है कि हिंदी डिक्शनरी में 'तू' शब्द का प्रयोग नकारात्मक नहीं है फिर भी, सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इसका प्रयोग एक स्पष्ट सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, और बौद्धिक तहुफ्कों को दर्शाता है। इस पूरे विवाद की कुंजी तू शब्द में छिपी है। चिकित्सक ने मरीज के प्रति तू-तड़ाक और रूखा व्यवहार अपनाया जो मरीज को नापसंद रहा, जाहिर है रहना भी चाहिए था और फिर उससे उपजा वो सारा विवाद व हिंसा। इस घटना के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक संघ द्वारा उक्त चिकित्सक के बचाव में आयोजित की गयी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रतिनिधि द्वारा यह कहना कि हम-उम्र लोगों के बीच 'तू' कहकर बात करना सामान्य है - अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक और अस्वीकार्य तथ्य यह है कि पूरे प्रदेश के मेडिकल संघ ने चिकित्सक राघव द्वारा मरीज पर किए गए शारीरिक हमले की स्पष्ट शब्दों में निंदा करने से पूरी तरह परहेज किया। जबकि यह पूरा मामला सोशल मीडिया के जरिये सार्वजनिक हो चुका था, तब भी मेडिकल संघों का गलत और हिंसा जैसे बुनियादी नैतिक प्रश्नों पर चुप रहना कोई साधारण चूक नहीं, बल्कि एक सूझी-बूझी संस्थागत खामोशी थी। यह खामोशी दरअसल जवाबदेही से बचने की रणनीति है, न कि किसी तटस्थता का प्रमाण। पेशागत संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सदस्यों का अंधा बचाव नहीं, बल्कि पेशे की नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा करें। जब एक पूरा पेशागत समुदाय, खुले तौर पर सामने आई हिंसा के बावजूद, उसे गलत कहने का नैतिक साहस नहीं दिखा पाता, तो यह केवल किसी एक व्यक्ति की विफलता नहीं रह जाती, बल्कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी के स्तर पर प्रोफेशनल एथिक्स का सामूहिक पतन बन जाती है। यह चुप्पी उस खतरे की ओर इशारा करती है, जहाँ पेशागत एकजुटता नैतिक विवेक से ऊपर रख दी जाती है और यहीं से संस्थाएँ अपने सामाजिक भरोसे को खोने लगती हैं। राघव ने जो हिंसा/ दुर्व्यवहार मरीज के साथ किया है वो स्पष्ट अपराध की श्रेणी में आता है, और किसी भी अपराधी का अपराध देखकर सजा सुनिश्चित की जाती है न की उसके योग्यता, उपलब्धियां तथा योगदान को देखकर। चलिए इसे समझने के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य पर गौर करें। मान लीजिये कोई भी एक साधारण व्यक्ति या फिर कोई मरीज एक सरकारी अधिकारी या अस्पताल में किसी चिकित्सक के साथ उनकी ड्यूटी के दौरान उन्हीं के दफ्तर या कार्यस्थल पर तू-तड़ाक से पेश आता है, क्या उस अधिकारी को यह भी उतना ही नार्मल रहेगा जितना कि चिकित्सक राघव द्वारा मरीज के प्रति व्यवहार को समझे जाने की चेष्टा या अपेक्षा हो रही थी क्या यह वाकई में स्वीकार्य होगा शायद नहीं। उस अधिकारी को तुरंत अपनी पद, इज्जत का एहसास होगा। ठीक यही एहसास एक मरीज को भी होता है जब एक सार्वजनिक सेवक उसके साथ इस लहजे में बात करता है। अस्पताल में प्रवेश करते ही मरीज की सामाजिक हैसियत, पेशा या उम्र गौण हो जाती है; वह सिर्फ एक पेशेंट बन जाता है। क्या रोगावस्था में भी कोई व्यक्ति गरिमा और सम्मानजनक व्यवहार का पात्र नहीं रहता आइये पहले भाषायी ढांचे में हिंदी के तू शब्द के प्रयोग को समझते हैं, दरअसल यह शब्द हमारी सामाजिक संरचना में गहरे पैठे हुए वर्चस्व का सूचक है। यह एक औपनिवेशिक और सामंती विरासत है जहाँ भाषा का इस्तेमाल तहुफ्कों बनाए रखने और अधीनस्थ की हैसियत याद दिलाने के लिए किया जाता रहा है। कोई उच्च पदासीन व्यक्ति अक्सर अपने से कम पद, कम आय, निम्न जाति या कम उम्र के व्यक्ति के प्रति तू का प्रयोग अपनी श्रेष्ठता के प्रदर्शन के तौर पर करता रहा है। आईजीएमसी की इस घटना में, तू डॉ. राघव के लिए शायद एक नॉर्मल आदत रही हो, लेकिन मरीज के लिए यह संस्थागत अहंकार और अपमान का प्रतीक था, जो किसी मरीज को उसकी असहायता की भावना को और गहरा कर सकती है। और पंजाब, हरियाणा से भिन्न शिमला समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में तू और आप का प्रयोग में स्पष्ट भिन्नता है। ऐसे मौकों पर आप यहां अपिमान्य है। कुछ इसी पूर्वाभ्यास को फिल्म 'कबीर सिंह' ने एक खतरनाक ग्लैमर प्रदान किया है। कबीर सिंह का चित्रण पेशेवर दक्षता के साथ-साथ एक भयंकर मैस्कुलिन/ अति पुरुषवादी व्यक्ति है जो बात-बात पर गुस्सा करता है, मारपीट करता है, न सम्मान की भाषा जानता है और न ही किसी तरह के पछतावा। सिर्फ अपनी ईगो की संतुष्टि के लिए जीता हुआ प्रतीत होता है।

आईजीएमसी के डॉ. राघव के व्यवहार में हमें कबीर सिंह के इसी सिनेमाई आदर्शीकरण का एक वास्तविक प्रतिबिंब देखने को मिलता है। यह दर्शाता है कि कैसे लोकप्रिय संस्कृति पेशेवर पावर के दुरुपयोग को कूल और शक्तिशाली के रूप में सामान्य बना कर पेश कर सकती है। इसके विपरीत, फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' प्रोफेसर अस्थाना के मुख से इसी अमानवीकरण की नीति को स्पष्ट शब्दों में कहलवाती है याद रखो, मरीज सिर्फ और सिर्फ एक बीमार शरीर है यानी उससे जुड़ाव या हमदर्दी पेशे में शामिल नहीं। डॉ. राघव का तू और हाथापाई, इस दृष्टिकोण की चरम परिणति है। जब मरीज सिर्फ एक बीमार शरीर है, तो उस बॉडी की भावनाएं, गरिमा या प्रतिक्रिया अप्रासंगिक हो जाती है। समस्या यह है कि यह बॉडी इंसान है, और उस इंसान ने अपना अधिकार जताया, जिसका जवाब हिंसा के साथ दिया गया। निष्कर्षतः, तू की यह लड़ाई केवल शब्दों की नहीं, बल्कि सम्मान, गरिमा और सार्वजनिक सेवा में शक्ति के समीकरण की लड़ाई है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति, अपनी उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति के बावजूद, पूंजीवादी उत्पादन-संबंधों के चंगुल में फंसती जा रही है। अस्पताल 'सेवा केंद्र' कम और 'स्वास्थ्य उद्योग' ज्यादा लगने लगे हैं। मरीज 'ग्राहक' बन जाता है और डॉक्टर-मरीज का रिश्ता एक लेन-देन का समझौता। इस व्यवस्था में करुणा, धैर्य और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य गौण हो जाते हैं। इस तथ्य के तमाम उदाहरण आप अपने आसपास लगभग प्रतिदिन घटते हुए अवश्य देखते होंगे। बहरहाल, चिकित्सक राघव का व्यवहार इसी नैतिक खोखलेपन का प्रतीक है। चिकित्सा नैतिकता की पहली शर्त है 'प्राइमम नॉन नोसेरे' - सबसे पहले, कोई नुकसान न पहुंचाए। यह नुकसान केवल शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी हो सकता है। एक पीड़ित, संभवतः मानसिक रूप से कमजोर मरीज के साथ 'तू-तड़ाक' और फिर हाथापाई करना, इस मूल सिद्धांत की घोर अवहेलना है। यह दर्शाता है कि पेशेवर प्रशिक्षण में क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन 'बेडसाइड मैनर्स' और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को गंभीरता से नहीं सिखाया जाता। मुन्ना भाई के प्रोफेसर का लेक्चर इसी भावनात्मक निषेध के कुतर्क को व्यवस्थित रूप देता है, जिसके खिलाफ फिल्म स्वयं विद्रोह करती है। घटना के बाद की प्रतिक्रियाएँ भी एक दिलचस्प सामाजिक नाट्य प्रस्तुत करती हैं। प्रशासन की झटकेदार प्रतिक्रिया पर गौर करते हैं- पहले निलंबन और फिर तत्काल बर्खास्तगी, सार्वजनिक रोष और मीडिया दबाव में लिया गया एक आत्मरक्षात्मक कदम लगता है। यह प्रदर्शित करता है कि प्रशासनिक तंत्र अक्सर संकट प्रबंधन के लिए सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि तात्कालिक जनता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। बर्खास्तगी एक गंभीर दंड है, और इसे बिना गहरी पारदर्शी जांच के लागू करना स्वयं एक प्रशासनिक दोष है। चिकित्सक समुदाय द्वारा तत्काल हड़ताल पर जाना एक सामूहिक पहचान की रक्षा का कृत्य था। यहाँ दो बातें सामने आती हैं- पहला, एक 'साथी की गलती पर भी एकजुट रहने' की सामंती/यूनियन संस्कृति, जो पेशेवर जवाबदेही के आगे एक आडंबर खड़ा करती है। दूसरा, चिकित्सकों की वास्तविक शिकायतें—जैसे अत्यधिक कार्यभार, अपर्याप्त सुरक्षा, और प्रशासनिक समर्थन की कमी—जो इस एक घटना के माध्यम से विस्फोटित हो गईं। हड़ताल ने अस्पतालों को ठप करके एक सामूहिक वार्ता की शक्ति प्रदर्शित की। और यहीं से घटना का सबसे पेचीदा पहलू सामने आता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पॉलिटेक्निक एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/[illegible])

आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें बैंक: सीडीओ

मुरादाबाद।

मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उद्योग विभाग, आईटीआई, श्रम विभाग, कौशल विकास मिशन और सेवायोजन विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उद्योग विभाग की सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की विस्तृत समीक्षा के दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र 4675 के सापेक्ष बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष में 9 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी मात्र 1663 स्वीकृति तथा 1549 आवेदन पत्रों पर वितरण की कार्यवाही की गयी है जो कि जनपद को आवंटित लक्ष्य 2900 के सापेक्ष 53 प्रतिशत ही प्रगति प्राप्त की गई है। समीक्षा में पाया गया कि उ.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा अब तक 53 प्रतिशत, यूको बैंक द्वारा 48 प्रतिशत, केनरा बैंक द्वारा 44 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 32 प्रतिशत, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 29 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 27 प्रतिशत स्वीकृति की प्रगति प्राप्त की गई है। बैठक में उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधियों जैसे उ.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा 15 स्वीकृति एवं 6 वितरण, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 12 स्वीकृति तथा 6 वितरण, केनरा बैंक द्वारा 20 स्वीकृति तथा 7 वितरण, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 20 स्वीकृति तथा 5 वितरण, यूको बैंक द्वारा 11 स्वीकृति तथा 8 वितरण, इण्डियन बैंक द्वारा 3 स्वीकृति तथा 2 वितरण, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1 वितरण, पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा 5 स्वीकृति कराने का बैठक में आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दूरभाष पर 12 स्वीकृति तथा 3 वितरण कराने का आश्वासन दियाा गया। इसके अतिरिक्त समस्त शेडयूल्ड बैंकों द्वारा आश्वासन दिया गया कि 31 जनवरी तक उनके द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 80

प्रतिशत की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जायेगी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आश्वासन दिया गया कि 31 जनवरी 2026 तक उनको आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत की प्रगति सुनिश्चित कर ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि जनवरी माह में उद्योग विभाग द्वारा बैंकों को आवंटित लक्ष्यों का 80 प्रतिशत प्रत्येक दशा में प्राप्त कर लिया जाये, यदि बैंकों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की जाती है, तो उनके उच्चाधिकारियों को इस सम्बंध में अवगत करा दिया जायेगा। उद्योग विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग जैसे उ.प्र. कौशल विकास मिशन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है। सेवायोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद को आवंटित रोजगार मेलों के वार्षिक लक्ष्य 46 के सापेक्ष दिसम्बर माह तक 45 मेलों की पूर्ति कर ली गई है
तथा मेले में चयनित अभ्यर्थियों के लक्ष्य 4650 के सापेक्ष 4953 की पूर्ति प्राप्त की जा चुकी है तथा कैरियर कांउसलिंग 90 के सापेक्ष अब तक 86 तथा प्रतिभागी अभ्यर्थियों के लक्ष्य 10500 के सापेक्ष 1×255 की पूर्ति प्राप्त कर ली गई है इसमें वृहद स्तर पर रोजगार मेला आयोजित करने के सम्बंध में अवगत कराया गया कि फरवरी 2026 में मेला आयोजित कराया जायेगा। श्रम विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मातृत्व शिशु तथा बालिका मदद योजना के अन्तर्गत अब तक 1253 आवेदन तथा कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत अब तक 1104 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। सहायक निदेशक कारखाना मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीकरण के वार्षिक लक्ष्य 210 (संशोधित 420) के सापेक्ष अब तक 149 कारखानों का नवीन पंजीकरण कराया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिन विभागों तथा बैंकों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई है उन्हें पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में योगेश कुमार संयुक्त आयुक्त उद्योग, अजीत कुमार कन्नौजिया सहायक श्रमायुक्त, योगेश कामेश्वर सहायक आयुक्त उद्योग, अमित कुमार सहायक निदेशक कारखाना, रत्नेश चन्द्र त्रिपाठी जिला सेवायोजन अधिकारी, जेपी सिंह कौशल विकास मिशन विभाग, मनोज कुमार मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, अरूण कुमार उ.प्र. ग्रामीण बैंक, मोहित कुमार प्रबन्धक कैनरा बैंक, नितिन कुमार सागर एलबीओ आदि उपस्थित रहे।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का रखा जाये विशेष ध्यान : डीएम

50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद मुरादाबाद में 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को डाटा अपडेशन पर विशेष ध्यान देते हुए ठीक प्रकार से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डाटा अपडेशन से रैंकिंग में सुधार आया है। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। निर्माण परियोजनाओं को हैण्डओवर करने से पूर्व ही समस्त कार्य दुरुस्त हों, इसको सुनिश्चित भी किया जाये। कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ द्वारा राजकीय प्रक्षेत्र रौण्डा के सुदृढ़ीकरण में भौतिक प्रगति धीमी होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राजकीय पौधशाला फहेतउझागंज निर्माण परियोजना का अपडेशन नहीं होने पर डीएम ने कार्यदायी संस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल अपडेशन किए जाने के निर्देश दिए। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एकेडमिक ब्लाक एवं बालिका छात्रावास भवन निर्माण की भौतिक प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष न होने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उ.प्र. जल निगम ग्रामीण द्वारा रुस्तमनगर सहसपुर में सोलर पैनल एवं मिट्टी भराव का कार्य कैम्पस में शेष रहने पर डीएम ने जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम द्वारा गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र मुरादाबाद के प्रशासनिक भवन, छात्रावास, आवासीय भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष नहीं होने पर डीएम ने कार्य में तेजी लाकर समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने उ.प्र. जल निगम नगरीय, यूपी सिडको, सीएनडीएस, उ.प्र. पर्यटन विकास निगम, उ.प्र. रा'य सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग,प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड प्रथम लोक निर्माण विभाग, नलकूप विभाग, उ.प्र. वक्फ विकास निगम लिमिटेड, पैकफेड आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी, जिला विकास अधिकारी जीबी पाठक एवं अन्य सबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहें।

रैली निकालकर यातायात नियमों के प्रति किया सचेत

मुरादाबाद। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 के अंतर्गत एक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। रोवर्स-रेंजर्स एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं और आम लोगों को राहवीर योजना तथा जीरो फेटेलिटी समाधान के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने एक जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने शहर के विभिन्न चौराहों पर राहगीरों को रोककर राहवीर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। छात्राओं ने बताया कि राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की जान बचाने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है। यह योजना लोगों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर चारु मेहरोत्रा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करके हम कई अनमोल जिंदगियां बचा सकते हैं। उन्होंने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग पर विशेष जोर दिया। रैली के दौरान, छात्राओं ने बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को रोका। उन्होंने ऐसे वाहन चालकों को सुरक्षा नियमों के प्रति सचेत किया और हेलमेट व सीट बेल्ट को जीवन रक्षक उपकरण बताया। इस कार्यक्रम का आयोजन रोवर्स-रेंजर्स अधिकारी प्रोफेसर एकता भाटिया एवं डॉ. प्रेमलता कश्यप, तथा एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सविता अग्रवाल एवं शिवानी गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अनुशासिका प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा, डॉ. रेनू शर्मा, डॉ. प्रीति पांडे आदि मौजूद रहे।

नगर पंचायत भटनी बाजार में हुई अहम बैठक, अतिक्रमण पर सख्त रुख

भटनी देवरिया।

फुटपाथ व सड़क किनारे कब्जे हटेंगे, मार्किंग के बाद उल्लंघन पर होगी कार्रवाई — विजय कुमार गुप्ता

नगर पंचायत भटनी बाजार के विकास एवं आम जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने की। बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था, सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ अतिक्रमण एवं जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर क्षेत्र के मेन रोड, सिनेमा रोड, विकास रोड, चूड़ा गली, चूबी गली तथा शिव मंदिर से आदर्श चौराहा तक सड़कों के चौड़ीकरण एवं आम नागरिकों के सुरक्षित और सुचारु आवागमन के लिए नगर पंचायत द्वारा पहले मार्किंग कराई जाएगी। इस कार्य के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो चिन्हित क्षेत्रों में निरीक्षण कर कार्रवाई करेगी। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि फुटपाथ एवं सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जा कर दुकानदारी या अन्य गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक और बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फुटपाथ पर किए गए कब्जे किसी भी स्थिति में हटाए जाएंगे और सड़क पर अतिक्रमण कर बैठे लोगों को हटाकर यातायात को सुचारु बनाया जाएगा।
अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि मार्किंग के बाद जो भी व्यक्ति निर्धारित सीमा का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध सख्त एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत का उद्देश्य नगर को अतिक्रमण मुक्त, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाना है। बैठक में उपस्थित सभासदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी नगर के विकास और व्यवस्था सुधार को लेकर अपने-अपने सुझाव रखे। नगर पंचायत प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन कर नगर को सुंदर और सुरक्षित बनाने में योगदान दें।

अधिवक्ताओं ने केक काटकर मनाई फातिमा शेख की जयन्ती

फतेहपुर।

देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख की जयंती बुद्ध पार्क के निकट कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता मो0 आसिफ एडवोकेट की अध्यक्षता में केक काट कर समारोहपूर्वक मनाई गई। जयन्ती समारोह में उपस्थित अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गया प्रसाद दुबे ने कहा कि फातिमा शेख ने महिलाओं के बीच शिक्षा की जो ज्योति जलाई थी, वो आज निरन्तर जल रही है। शिक्षा की वजह से ही आज महिलाएँ अपने अधिकार को प्राप्त कर भारत को गौरान्वित कर रही हैं। बाल कल्याण समिति की सदस्य तरन्नुम नाज़ ने कहा कि फातिमा शेख ने महिलाओं हेतु स्कूल खोला, जो महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उन्हीं की देन है कि आज तमाम सामाजिक कुरीतियों से बचकर महिलाएं सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हैं। सब इंस्पेक्टर महिला थाना आशा पांडेय्य ने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। जब महिला की बात आती है तो शिक्षा और भी ज़रूरी हो जाती है। इसलिए बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए। जयन्ती समारोह की अध्यक्षता करते हुए मो0 आसिफ

एडवोकेट ने इतिहास से अवगत कराते हुए कहा कि 1848 में लड़कियों, विशेष रूप से दलित और मुस्लिम समुदाय की बहन-बेटियों को शिक्षित करने में फातिमा शेख का योगदान अविस्मरणीय है। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ दलित व मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जब सावित्रीबाई फुले को घर से निकाला गया, तब फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने फुले दंपति को सहारा दिया। स्कूल में अध्यापकों की अनुपलब्धता के समय भी फातिमा शेख ने बालिकाओं को पढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसीलिए फातिमा शेख को दलित-मुस्लिम एकता के ध्वजवाहक के रूप में याद किया जाता है। अन्त में उन्होंने सभी का आभार जताते हुए धन्यावाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बार एशोसियेशन के महामंत्री जितेन्द्र सिंह एडवोकेट, नरोत्तम सिंह एडवोकेट, वीर प्रकाश लोधी एडवोकेट, श्रवण कुमार गौड़ एडवोकेट, वीर सिंह एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता मालती देवी, रूही एडवोकेट, अनुज दिक्षित एडवोकेट, अजलाल फारुकी एडवोकेट, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक मो0 कासिम, बार एशोसियेशन के पूर्व महामंत्री बचानी लाल एडवोकेट, पूर्व महामंत्री आशीष गौड़, पूर्व महामंत्री मणि प्रकाश दुबे, चंद्रपाल मौर्य एडवोकेट, ममनून एडवोकेट, आसिफ मक़सूद एडवोकेट, मलखान सिंह, अत्तहियात एडवोकेट, शकील एडवोकेट, सुरेन्द्र गौतम एडवोकेट, बौद्ध प्रिय गौतम एडवोकेट, मोहम्मद गुलफाम खान एडवोकेट, माया गौतम एडवोकेट, रुखसार एडवोकेट, अलफिशा एडवोकेट, दिव्या एडवोकेट, दानिशी एडवोकेट, यासीन एडवोकेट, मोहम्मद यासीन एडवोकेट, मिर्जा असद बेग एडवोकेट, व्यापारी नेता बृजेश सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता शिव प्रसाद, दिलशाद अली, गाज़ी अब्दुर रहमान गनी, दिलशाद अहमद, धीरज कुमार बाल्मीकि, शोएब अहमद अरबी, इरशाद हुसैन, प्रकाश अम्बेडकर, नरेश पासी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

शिक्षा से ही भारत को गौरान्वित कर रहीं महिलाएं- गया प्रसाद दुबे
सामाजिक कुरीतियों से बचकर आगे बढ़ रही आधी आबादी-तरन्नुम नाज़
शिक्षा जीवन का आधार, बेटियों को दिलाएं अच्छी शिक्षा-आशा पाण्डेय
बहन-बेटियों को शिक्षित करने में फातिमा शेख का योगदान अविस्मरणीय-मो0 आसिफ

दिल्ली में जल संकट की क्या है बड़ी वजह, विधानसभा में मंत्री प्रवेश वर्मा गिनाने लगे कारण

नई दिल्ली। राजधानी में गंदे और दूषित पानी की शिकायतें बढ़ने के बीच जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि दिल्ली में जल प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पुरानी और टूटी हुई पाइपलाइनें हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह पूरी व्यवस्था पिछली सरकार से विरासत में मिली है, जिसमें सुधार करना आसान नहीं है। उनके अनुसार दिल्ली में लगभग 5,200 किलोमीटर पाइपलाइनें ऐसी हैं, जिन्हें बदले बिना साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना मुश्किल है।

30-40 साल पुरानी पाइपलाइनों से सप्लाई

मंत्री ने बताया कि दिल्ली में कुल लगभग 16,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, जिनमें से कई इलाकों में पाइपलाइनें 30 से 40 साल पुरानी हैं। इन पाइपलाइनों में जगह-जगह रिसाव है और कई जगह सीवर लाइनें इनके साथ मिल जा रही हैं, जिसके कारण पानी दूषित होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि राजधानी के कई हिस्सों में बार-बार गंदे पानी की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

7200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछले 11 महीनों में जल विभाग से जुड़े 7,200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य पुरानी पाइपलाइनों को बदलना, पानी का सही वितरण करना और नई तकनीक के जरिए 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि राजधानी के करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों में पुरानी पाइपलाइनों को बदलने का काम पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि बाकी इलाकों में भी जल्द ही काम शुरू होगा।

पिछली सरकार को घेरा

मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान जाइका और एडीबी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं वर्षों तक लटकी रहीं। उनके अनुसार यदि ये प्रोजेक्ट समय पर शुरू हो जाते, तो आज दिल्ली में जलप्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं को दोबारा शुरू किया है और अब काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

साफ जल, सरकार की पहली प्राथमिकता

प्रवेश वर्मा ने आश्वासन दिया कि जल्द ही दिल्लीवासी बदलाव महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी जल व्यवस्था को सुधारने में समय लगेगा, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को साफ पानी मिले। वर्मा ने यह भी कहा कि जलप्रदूषण पर नियंत्रण करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और आने वाले समय में गंदे पानी की शिकायतों में कमी देखने को मिलेगी।

बजट 2026: राष्ट्रपति ने दी मंजूरी; दो चरणों में चलेगी कार्यवाही

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से होगा शुरू

नई दिल्ली । भारत सरकार की सिफारिश पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा, और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से एकत्रित होगी, जो सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के संसदीय बजट सत्र के कार्यक्रम को औपचारिक मंजूरी दे दी है। सरकार की सिफारिश पर लिए गए इस निर्णय के अनुसार, संसद का आगामी बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। यह सत्र देश के आगामी वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए आर्थिक खाका तैयार करने दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

बजट कब पेश होगा?

आम तौर पर हर वर्ष वित्त मंत्री 1 जनवरी को बजट पेश करती हैं। इस बार 1 फरवरी को रविवार है। इसलिए इस बार बजट कब पेश होगा? इसे लेकर अटकलें लग रही थीं। हालांकि, बजट सत्र के कार्यक्रम को देखकर यह तय माना जा रहा है कि इस बार भी बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। हालांकि माना जा रहा है संसदीय कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित रखने और सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने के लिए इस बार के बजट सत्र को दो चरणों में विभाजित किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शेड्यूल इस प्रकार रहेगा-

पहला चरण- सत्र की शुरुआत 28 जनवरी 2026 को होगी। यह चरण लगभग दो सप्ताह तक चलेगा और 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा.

अवकाश - पहले चरण की समाप्ति के बाद संसद की कार्यवाही में विराम रहेगा। इस दौरान संसदीय समितियां आम तौर पर विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन करती हैं।

दूसरा चरण- अवकाश के बाद संसद 9 मार्च 2026 को फिर से एकत्रित होगी।

बजट सत्र का समापन कब?

सत्र का समापन 2 अप्रैल 2026 को होगा। आधिकारिक घोषणा में इस शेड्यूल को -सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन- की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। 9 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे चरण में बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही वर्ष 2026 के सबसे महत्वपूर्ण संसदीय सत्र की समय सारिणी तय हो गई है। 28 जनवरी से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया देश की आर्थिक नीतियों और विधायी कार्यों के लिए मंच तैयार करेगी।

कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर जबरदस्त हंगामा, ईडी की छापेमारी केस पर सुनवाई स्थगित

भारी भीड़ और हंगामे से जज नाराज; बेंच छोड़कर बाहर निकलीं

नई दिल्ली। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे जैसे ही जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच में सुनवाई शुरू होने वाली थी, वहां वकीलों और इंटर्न की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति यह थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। जस्टिस घोष ने भीड़ को देखते हुए उन वकीलों और इंटर्न को बाहर जाने को कहा जो इस केस से नहीं जुड़े थे। उन्होंने 5 मिनट का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर भीड़ कम नहीं हुई, तो वह सुनवाई नहीं करेंगी। टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने भी लोगों से बाहर जाने की अपील की, लेकिन वकीलों के बीच धक्का-मुक्की और बहस शुरू हो गई। अव्यवस्था से नाराज होकर जस्टिस घोष सुनवाई स्थगित कर चली गईं। केंद्रीय एजेंसी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छापेमारी के दौरान मौके पर पहुंचकर जांच में बाधा डाली। सीएम अपने साथ पुलिस बल लेकर आईं और वहां से कई महत्वपूर्ण फाइलें, दस्तावेज और लैपटॉप जबरन उठा ले गईं। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। टीएमसी का कहना है कि चुनाव से पहले पार्टी की रणनीतियों को चुराने के लिए जानबूझकर यह छापेमारी की गई है। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, 13 जनवरी को अगली सुनवाई

नई दिल्ली ।

दिल्ली स्थित तीस हजारी कोर्ट ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी के मामले के सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अदीब, कैफ, काशिफ, अदनान और समीर ने तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. तीस हजारी कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है. कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी पांच आरोपियों के मेडिकल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है. आरोपियों के वकील ने आरोप लगाया कि सभी पांच आरोपियों को जेल के अंदर पीटा गया. एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव को फैज-ए-इलाही मस्जिद पत्थरबाजी मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया गया है. वह इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे हैं. इसके साथ ही दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 8 आरोपियों की ज्यूडिशियल कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और उकसाने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से पूछताछ

उधर, दिल्ली पुलिस द्वारा उन 10 इन्फ्लुएंसर की पहचान करने के बाद एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर अफवाह फैलाई थी कि अदालत के आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीमों द्वारा एक वीडियो को देखने के बाद महिला को बुलाया गया था, जिसमें उसने कथित तौर पर दावा किया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में

प्रदूषण पर प्रहार : सीएक्यूएम ने दिए एनसीआर में 16 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश, उल्लंघन पर चेताया

नई दिल्ली । वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को तेजी से कम करने के लिए सख्त कदम उठाते हुए 16 औद्योगिक इकाइयों को तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ये इकाइयां गंभीर और बार-बार होने वाले पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के दोषी पाई गईं। निरीक्षण के दौरान पता चला कि इन इकाइयों ने संचालन की सहमति (सीटीओ) और स्थापना की अनुमति (सीटीई) के बिना काम किया, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) नहीं लगाए या उन्हें ठीक से नहीं चलाया, प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल किया, ग्रेप की रोक अवधि में भी संचालन जारी रखा, डीजल जनरेटर सेट के नियमों की अनदेखी की तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं से खुला धुआं और उत्सर्जन किया। सीएक्यूएम के एक अधिकारी के अनुसार, इन 16 इकाइयों में से 14 हरियाणा के सोनीपत जिले में, एक उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में और एक राजस्थान (एनसीआर) में स्थित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये इकाइयां तब तक बंद रहेंगी, जब तक वे सभी आवश्यक पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पूरा पालन नहीं कर लेतीं। सीएक्यूएम ने चेतावनी दी है कि गैर-अनुपालन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी इकाइयों के खिलाफ बंद करने के अलावा जुर्माना तथा अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आयोग ने एनसीआर में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन करें, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को ठीक से स्थापित और संचालित रखें और हर समय अनुपालन सुनिश्चित करें।

हिमाचल के सिरमौर में खाई में गिरी बस, हादसे में नौ लोगों की मौत

सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुरधार में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर 400 मीटर खाई में गिर गई है। इस हादसे में नौ लोगों के मारे जाने की सूचना है। इस दर्दनाक हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। वहीं, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अभी तक करीब 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, जीत कोच बस शिमला जिला के कुपवी से सोलन जा रही थी। कोहरे और ठंड के कारण सड़क पर फिसलन था। इसके चलते बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। स्थानीय लोग हादसे में घायलों को बाहर सड़क तक लेकर आ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर चीखो पुकार मची है। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए हैं। एसपी सिरमौर, निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि सिरमौर जिले में हरिपुरधार के पास कुपवी से शिमला जा रही एक प्राइवेट बस के सड़क से नीचे गिरने से हुए हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 30-35 लोग सवार थे। और जानकारी का इंतजार है। मैं मौके पर जा रहा हूं। पुलिस और दूसरी बचाव टीमें घायलों को निकालने की कोशिश कर रही हैं।

चाइना को ठेके, डोनाल्ड ट्रम्प पर चुप्पी! खरगे ने कहा- पीएम नरेन्द्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी आत्मसमर्पण है

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर उन खबरों को लेकर हमला बोला जिनमें कहा गया था कि भारतीय सरकार सरकारी ठेकों के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर लगे पांच साल पुराने प्रतिबंध को हटाने की योजना बना रही है।

उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति में असंगति का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि भारत की विदेश नीति एक बेकाबू पेंडुलम की तरह झूलती है और साथ ही भारत की विदेश नीति में असंगति की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मैं देश को झुकने नहीं दूंगा वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए खरगे ने कहा कि मौजूदा स्थिति इस दावे के बिल्कुल उलट है। खरगे ने x पर पोस्ट किया कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। आज जो हो रहा है, वह ठीक इसका उल्टा है। दो हालिया उदाहरण- चीनी कंपनियों पर 5 साल से लगा प्रतिबंध हटाया जा रहा है। गलवान में हमारे बहादुर भारतीय सैनिकों के बलिदान का मोदी ने चीन को क्लीन चिट देकर अपमान किया। अब चीनी कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछाकर, वह दिखा रहे हैं कि उनकी लाल आंखों में लाल रंग कितना गहरा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के रूसी तेल निर्यात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की भी आलोचना करते हुए इसे आत्मसमर्पण का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प रोजाना भारत के रूसी तेल निर्यात पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन मोदी चुप हैं। वह अपनी आंखें फेर रहे हैं। सर वाली बात आत्मसमर्पण जैसी लगती है। हमारे लिए विदेश नीति का मतलब है राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना। लेकिन मोदी सरकार ने हमारी गुटनिरपेक्ष और रणनीतिक स्वायत्तता वाली विदेश नीति को करारा झटका दिया है। खरगे ने आगे कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति एक बेकाबू पेंडुलम की तरह डगमगाती है, कभी इधर, कभी उधर, और इसका खामियाजा भारत की जनता भुगत रही है। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई घातक झड़प के बाद चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। यह संभावित बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन अमेरिका के दबाव के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल, प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई थी।

लालू और राबड़ी पर आरोप तय, राउज़ एवेन्यू का अहम फैसला

नई दिल्ली ।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाले में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए। अदालत ने नियुक्तियों के पीछे एक व्यापक साजिश के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले को भी स्वीकार किया।

राउज़ एवेन्यू अदालत ने आरोप तय करने के लिए मामले को 29 जनवरी को सूचीबद्ध किया है। अगली तारीख को, अदालत आरोपियों के बयान को दर्ज करेगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप तय करने का आदेश पारित करते हुए कहा कि संदेह के आधार पर लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से एक व्यापक साजिश मौजूद थी। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूत इस स्तर पर घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। 19 दिसंबर को, सीबीआई द्वारा लालू यादव और अन्य के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपों पर फैसला 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने मामले में आरोपियों की स्थिति के संबंध में एक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि उसके आरोप पत्र में नामित 103 आरोपियों में से पांच की मृत्यु हो चुकी है।

एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 13 जनवरी को अर्जियों पर सुनवाई

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अंतिम सुनवाई 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिन में इन याचिकाओं की सुनवाई तय की थी, लेकिन बाद में कहा कि वह मंगलवार (13 जनवरी) को कार्यवाही फिर से शुरू करेगी। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी मामले में अपनी दलीलें फिर से पेश करने वाले थे। 6 जनवरी को, निर्वाचन आयोग ने पीठ को बताया था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का अधिकार और क्षमता उसके पास है, साथ ही यह सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है कि किसी भी विदेशी को मतदाता के रूप में पंजीकृत न किया जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कार्यवाही मंगलवार को फिर से शुरू की जाएगी। मामले में चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को अपने तर्क आगे बढ़ाने थे। 6 जनवरी को चुनाव आयोग ने पीठ को बताया था कि उसके पास मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की शक्ति और क्षमता है, और इसके साथ ही यह संवैधानिक दायित्व भी है कि कोई भी विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो। इन याचिकाओं में बिहार सहित कई राज्यों में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई है और इनमें चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमा, नागरिकता तथा मतदान के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं।

पीएम मोदी का गुजरात दौरा- सोमनाथ में ओंकार जाप, ड्रोन शो में भी होंगे शामिल

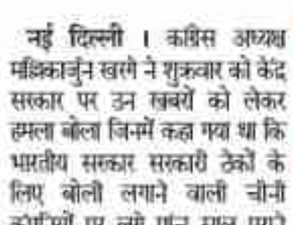

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी 2026 तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 10 जनवरी की शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, वे रात करीब 8 बजे ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो देखेंगे। बयान के अनुसार, 11 जनवरी को सुबह करीब 9:45 बजे, प्रधानमंत्री मोदी शौर्य यात्रा में भाग लेंगे, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित एक औपचारिक जुलूस है। इसके बाद, सुबह करीब 10:15 बजे, प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे, प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिन में आगे, प्रधानमंत्री कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजकोट जाएंगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे, वे सम्मेलन में आयोजित व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दोपहर लगभग 2 बजे, प्रधानमंत्री राजकोट स्थित मारवाड़ी विश्वविद्यालय में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

आतंकवाद पर अब होगा 'Digital Strike', अमित शाह बोले- एनआईडीएमएस बनेगा देश का सुरक्षा कवच

नई दिल्ली । भारत की पहली राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (एनआईडीएमएस) का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ अगली पीढ़ी का सुरक्षा कवच बनेगी और देश में होने वाली सभी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं की जांच और उनके विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण में आने वाले दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली तीन प्रमुख तरीकों से मजबूत होगी। शाह ने गुरुग्राम के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) छावनी में एनआईडीएमएस का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए यह बयान दिया। यह भारत की आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विरोधी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक, एनएसजी के महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक और विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे। एनएसजी द्वारा विकसित एनआईडीएमएस एक सुरक्षित, राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) से संबंधित डेटा का व्यवस्थित संग्रह, संकलन और प्रसार करना है। शाह ने अपने संबोधन में कहा, देश में होने वाली सभी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं की जांच और उनके विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के लिए एनआईडीएमएस आने वाले दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा, एनआईडीएमएस आतंकवाद के खिलाफ अगली पीढ़ी का सुरक्षा कवच बनेगा। मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्र किए हैं, लेकिन अब तक वे अलग-अलग थे। भाजपा नेता ने कहा, अब हम इन सभी डेटा स्रोतों को आपस में जोड़ने और उनके विश्लेषण के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज एनआईडीएमएस का शुभारंभ इस प्रक्रिया को गति देगा और देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।